International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol. 11 No. 3 Jan-Feb 2024

ईरान में चीन का प्रभाव एवं भारतीय हितों को चुनौती

मुकेश कुमार प्रजापति
सहायक आचार्य, रक्षा एवं स्त्रातजीय अध्ययन विभाग,
श्री राम किशुन कॉलेज गोकुल, करसड़ा, वाराणसी- 221011, यू.पी.
Corresponding Author – मुकेश कुमार प्रजापति
Email:- mukeshprj89@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.10725549

सारांश:-

भारत की स्वतंत्रता के पहले व बाद में भी भारत का ईरान के साथ सांस्कृतिक व व्यापारिक सम्बन्ध रहा है। वर्तमान समय में भी भारत के द्वारा ईरान में विभिन्न परियोजनाओं में निवेश किया गया है। भारत का ईरान के साथ रणनीतिक साझेदारी के साथ-साथ भारत, ईरान का सबसे बड़ा तेल आयातक देश रहा है। हाल के वर्षों से इस क्षेत्र में चीन अपने भारी निवेश के कारण न सिर्फ ईरान में बल्कि खाड़ी देशों की क्षेत्रीय भू-राजनीति को नियंत्रित करने में लगा है। भारत, ईरान की विभिन्न परियोजनाओं के विकास और निर्माण में भारी निवेश किया है ईरान का चीन की बेल्ट एण्ड रोड इनीशिएटिव में जुड़ने के बाद से ही भारतीय हितों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रस्तावना:-

भारत एवं ईरान फारसी साम्राज्य और भारतीय साम्राज्यों के युग से ही घनिष्ठ सभ्यतागत संबंध रखते हैं। भारत के पड़ोस में ईरान एक महत्त्वपूर्ण देश है। वस्तुतः वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से पहले तक दोनों देश सीमा भी साझा करते थे। मध्य-पूर्व में स्थित ईरान एकमात्र शिया बहुल राष्ट्र है। भारत और ईरान ने 15 मार्च 1950 को एक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए, और 1979 की ईरानी क्रांति से पहले, ईरान के शाह ने दो बार मार्च 1956 और फरवरी 1978 में भारत का दौरा किया। भारत की आज़ादी के बाद वर्ष 1963 में ईरान की यात्रा पर जाने वाले तात्कालिन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू पहले भारतीय थे।[1] प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अप्रैल 2001 में ईरान यात्रा के दौरान **तेहरान घोषणा** पर हस्ताक्षर किया गया। उसके बाद राष्ट्रपति सैय्यद मोहम्मद खातमी की यात्रा और 2003 में नई दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर ने भारत-ईरान सहयोग को गहरा किया। दोनों दस्तावेज़ों ने सहयोग के क्षेत्रों की पहचान की और भारत-ईरान साझेदारी के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण निर्धारित किया।[2] ईरान के विशाल गैस, तेल और हाइड्रोकार्बन भंडार के साथ-साथ इसकी रणनीतिक स्थिति और व्यापारिक दृष्टिकोण से यह क्षेत्र भारत के लिए एक अहम चेक प्वाइंट है। ईरान जहाँ भारत की ऊर्जा ज़रूरतों के बड़े हिस्से को पूरा करता है, वहीं भारत द्वारा ईरान को दवा, भारी मशीनरी, कल-पुर्जे और अनाज का निर्यात किया जाता है। सामरिक तौर पर दोनों देश एक-दूसरे के पुराने सहयोगी हैं। अफगानिस्तान, मध्य एशिया और मध्य-पूर्व में दोनों देशों के साझा सामरिक हित भी हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में दूतावास के अलावा जाहिदाद और बंदरअब्बास शहर में भारत के वाणिज्य मिशन हैं। भारतीय कंपनियाँ ईरान में कारोबार की बड़ी संभावनाएँ देखती हैं। ईरान के तेल रिफाइनरी, दवा फर्टिलाइज़र और निर्माण क्षेत्र में भारतीय कंपनियाँ अरबों डॉलर का निवेश रही हैं।

भारत के लिए ईरान का महत्व:-

ईरान, भारत के लिए काफी अहम है क्योंकि ईरान के रास्ते भारत मध्य एशियाई देश- तज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाखस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व रूस और अफगानिस्तान जैसे देशों से आसानी से व्यापार कर सकेगा। भारत के सहयोग से चाबहार बंदरगाह का भी विकास किया गया है। भारत के लिये चाबहार बंदरगाह का आर्थिक महत्व है जिसके द्वारा वह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में होने वाली घटनाओं पर नज़र रख सकता है। चाबहार ईरान का एक तटीय शहर है, जो देश के दूसरे सबसे बड़े प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान में स्थित है। यह ओमान की खाड़ी से सटा ईरान का इकलौता बंदरगाह है। यह बंदरगाह ईरान के दक्षिणी समुद्र तट को भारत के पश्चिमी समुद्री तट से जोड़ता है। चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिणी-पूर्वी समुद्री किनारे पर स्थित है। यह पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह के पश्चिम में मात्र 72 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बंदरगाह के विकास के लिए भारत और ईरान के बीच 2003 में आम सहमति बनी थी। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र

मोदी मई 2016 में ईरान की यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा मिला। यात्रा के दौरान, **"सभ्यतागत संपर्क, समकालीन संदर्भ" (Civilizational Connect, Contemporary Context)** शीर्षक से एक संयुक्त बयान जारी किया गया और 12 एमओयू/समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। यात्रा के दौरान भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार, परिवहन और पारगमन पर त्रिपक्षीय समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति रूहानी ने फरवरी 2018 में भारत का दौरा किया, जिसके दौरान **"ग्रेटर कनेक्टिविटी के माध्यम से समृद्धि की ओर" (Towards Prosperity Through Greater Connectivity)** शीर्षक से एक संयुक्त बयान जारी किया गया था। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने 13 एमओयू/समझौतों पर हस्ताक्षर किए।[3] इसके तहत भारत को बंदरगाह के कुछ हिस्सों के विकास के लिए 10 साल की लीज़ मिली। भारत ने 2018 में पोर्ट के एक टर्मिनल का संचालन भी अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद से भारत ने वहाँ से अफ़ग़ानिस्तान को काफ़ी कुछ सामान निर्यात भी किया है जिनमें अनाज और खाने की चीज़ें शामिल हैं। साथ ही, **चाबहार-ज़ाहेदान रेलवे** (Chahbahar-Zahedan Railway) बनाने के लिए भारत को ठेका दिया गया जो सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी है। ज़ाहेदान से अफ़ग़ानिस्तान की सीमा लगभग 40 किलोमीटर दूर है। इस रेल लाइन को ईरान के चाबहार से अफ़ग़ानिस्तान के ज़ेरांज (Zaranj) प्रांत तक ले जाने की योजना है। और अगर ये रेल लिंक बन जाता तो मालगाड़ी से भारतीय सामानों को आसानी से अफ़ग़ानिस्तान तक पहुँचाया जा सकता है।[4]

विदेश मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने जुलाई और अगस्त 2021 में तेहरान का दौरा किया और राष्ट्रपति सैय्यद इब्राहिम रायसी से मुलाकात की। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने जून 2022 में भारत का दौरा किया। यात्रा के दौरान, नागरिक और वाणिज्यिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अगस्त 2022 में, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ईरान का दौरा किया, जिसके दौरान ईरान और भारत के बीच असीमित यात्राओं को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधान मंत्री मोदी और राष्ट्रपति रायसी ने पहली बार सितंबर 2022 में समरकंद, उज्बेकिस्तान में एससीओ राष्ट्र प्रमुखों के शिखर सम्मेलन के मौके पर मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग, विशेष रूप से व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं की अगस्त 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर भी मुलाकात हुई थी।[5]

ईरान में चीन का प्रभाव:- ईरान का वर्ष 2013 में बेल्ट एण्ड रोड इनीशिएटिव में जुड़ने के बाद से चीन की उपस्थिति बढ़ने लगी। अभी हाल में चीन की उपस्थिति जहाँ एक ओर भारतीय हितों के समक्ष चुनौती खड़ी कर दी है, वहीं दूसरी ओर भारत का ईरान में वर्षों से अरबों डॉलर के निवेश पर पानी फेर दिया है। हाल ही में चीन और ईरान ने बेल्ट एंड रोड पहल के तहद 24 मार्च 2021 को एक व्यापक सैन्य और **"व्यापक रणनीतिक साझेदारी"** समझौता पर हस्ताक्षर किया। दोनों देशों के बीच हुआ यह रणनीतिक और व्यापारिक समझौता अगले 25 वर्षों तक मान्य होगा, इस दौरान ईरान के प्रमुख क्षेत्र, जैसे कि ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में लगभग 400 बिलियन डॉलर के चीनी निवेश का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। ईरान, चीन को अगले 25 वर्षों तक नियमित रूप से बेहद सस्ते दरों पर कच्चा तेल और गैस मुहैया कराएगा। प्रस्तावित निवेश चीन द्वारा अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के एक हिस्से के रूप में किसी भी देश के लिए अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। ईरान के तेल, गैस और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में क्रमशः $280 बिलियन और $120 बिलियन डॉलर के निर्माण में भारी व्यय के लिए प्रस्तावित किया गया है। बीजिंग ईरान में अपने निवेश की रक्षा के लिए 5,000 से अधिक चीनी सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने की भी योजना बना रहा है।[6] जुलाई 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा, चीनी निर्माण कंपनियां ईरान की खाड़ी तट रेखा के साथ कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करने के लिए तैयार हैं, जिसमें **शात अल-अरब** (Shatt Al-Arab River) नदी के पूर्वी तट पर एक शहर **अबादान** (Abadan) में मुक्त-व्यापार क्षेत्र और **केशम** (Qeshm) द्वीप शामिल हैं, जहाँ तेहरान तेल उत्पादन और भंडारण के लिए एक प्रमुख केंद्र की योजना बना रहा है। ईरान द्वारा हाल ही में **फरज़ाद-बी तेल** (Farzad-B oilfield) क्षेत्र से भारत को बाहर कर दिया गया है, एक ऐसी परियोजना जिसमें भारत 2002 से शामिल था। हालांकि भारत पहले ही फरज़ाद-बी तेल क्षेत्र परियोजना पर 400 मिलियन डॉलर से अधिक खर्च कर चुका था।[7] मध्य एशियाई देशों के लिए ईरान और अफगानिस्तान के साथ एक संस्थागत संरचना बनाने में भारत के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार के लिए भारत के लिए प्रवेश बिंदु भी है। हालांकि ईरान के विकास के लिए विदेशी निवेश से भारत को किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है। बल्कि चीनी प्रभाव ईरान में भारत के विकल्प को खत्म कर देगा, जिसके माध्यम से

भारत अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रूस और यूरोप तक व्यापार करने की योजना बना रहा है। इस क्षेत्र में चीन का निवेश भारत के उन सभी प्रस्तावित परियोजनाओं और नीतियों को प्रभावित करेगा जिसके लिए भारत ने अरबों डालर खर्च किए हैं। भारत के **पश्चिम एशिया नीति** (Look West Policy) में खाड़ी देशों का प्रमुख स्थान है जिसमें ईरान को केन्द्रबिन्दु के रूप में माना जाता है।

ईरान में चीन के प्रभाव से जहाँ एक ओर इस खाड़ी देश निहित भारत के हित प्रभावित होगें वहीं दूसरी ओर भारत की पूर्व में प्रस्तावित नीतियों एवं परियोजनाओं के ऊपर भी ग्रहण लग सकता है। जिसमें **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण पारगमन गलियारा** (International North-South Transitt Corridor) प्रमुख है। इस गलियारा के द्वारा भारत जहाँ एक ओर ईरान से व्यापार करता वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान में भी अपने सामानों का निर्यात कर सकता है। हालांकि भारत ने ईरान के **ज़रांग** से अफ़ग़ानिस्तान के **डेलाराम** तक गेहूँ भेज चुका है। इसके अलावा इसी मार्ग के माध्यम से भारत मध्य एशियाई देशों एवं रूस से सस्ती दर में गैस व कच्चा तेल का आयात भी कर सकता है। आगे इसी मार्ग के द्वारा यूरोपीय देशों को भी जोड़ना प्रस्तावित है जिससे भारत के व्यापार लागत मूल्य को कम किया जा सकता है।

मानचित्र संख्या-(1), अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण पारगमन गलियारा

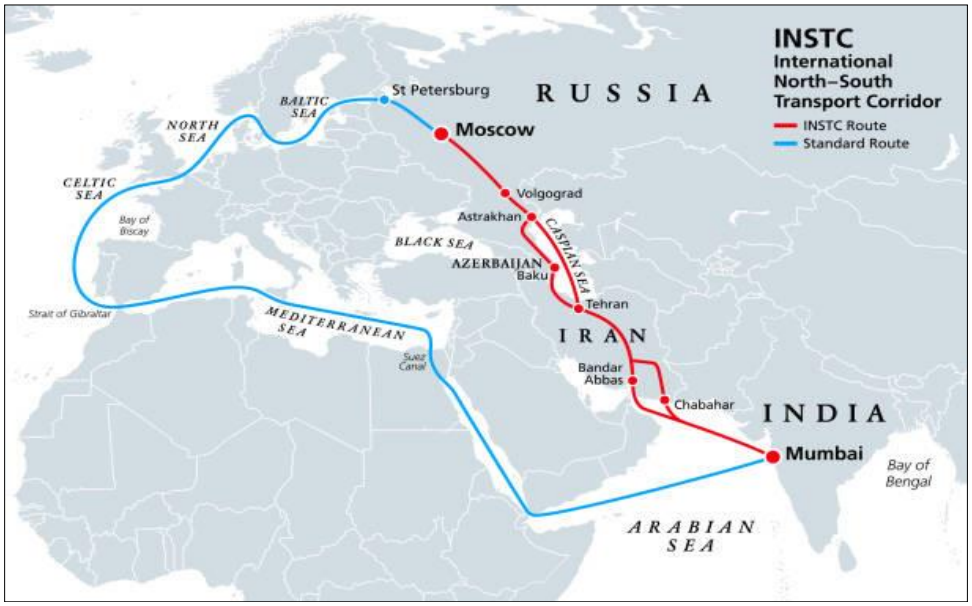

स्रोत-8

चीन का ईरान के चाहबहार बंदरगाह के विकास में भारी निवेश के कारण ही इसके 5 में से 3 टर्मिनल पर चीन का कब्जा है। वर्तमान समय में भारत से अधिक ईरान में चीन का निवेश है, जो भविष्य में इस क्षेत्र में चीन की पकड़ को और मजबूत बना सकता है। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर चीन की नौसेना पहले से ही मौजूद है, यदि चाहबहार बंदरगाह पर भी चीन का दबदबा हो गया तो निश्चत तौर पर भारतीय हितों को प्रभावित करेगा। इसके अलावा चीन के द्वारा ईरान के **जस्क द्वीप** को भी विकसित करने की बात चल रही है जो **स्ट्रेट होर्मूज़** के पास है, यदि ऐसा होता है तो इससे भारतीय व्यापार बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। इसके अलावा **चाबहार-ज़ाहेदान रेलवे** परियोजना जिससे ईरान ने भारत को अलग कर दिया है, हो सकता है इसमें चीन को शामिल कर ले। इस प्रकार से चीन का भारी निवेश ईरान में भारत के लगभग सभी परियोजनाओं पर ग्रहण लग सकता है। कुछ नीति निर्माता ईरान के प्रति भारत की ढुलमुल नीति को जिम्मेदार मान रहें हैं-

पूर्व राजदूत **केसी सिंह** ने कहा, "ऐसे प्रोजेक्ट तभी बनते हैं जब दोनों के बीच रिश्ते सही हों। अगर ईरान महसूस करता है कि आप अमरीका से डरकर उससे बात नहीं कर रहे तो वो आपके साथ प्रोजेक्ट क्यों करेंगे? अगर उनको चीन का पैसा मिल गया है, तो चीन के पैसे से प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे।" प्रोफ़ेसर **पाशा** कहते हैं कि अगर ये मामला ऐसे ही चलता रहा, तो चाहबहार पोर्ट की लीज़ का एक्सटेंशन भी ख़तरे में है। भारत-ईरान के रिश्तों के भविष्य के बारे में वो कहते हैं, "छोटे-छोटे झटकों से ही बड़े झटकों की शुरूआत होती है। ये सब झटके होते आ रहे हैं - रेल का प्रोजेक्ट, गैस फ़ील्ड का प्रोजेक्ट, और भी कई प्रोजेक्ट नहीं हो पाए हैं, व्यापार भी कम हो गया है, तो आप समझ जाइए कि ईरान क्यों नहीं नाराज़ होगा." प्रोफ़ेसर पाशा के शब्दों में, "ईरान के हुक्मरान अब तय कर रहे हैं कि भारत की ओर जो दोस्ती था, वो अब ठंडा होता जा रहा है।"[9] जापान के निक्की अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ,दोनों देशों की रणनीतिक

साझेदारी, विश्व ऊर्जा बाजार को बदलकर रख सकती है। क्योंकि आज भी ऊर्जा और तेल की अंतरराष्ट्रीय समीकरणों में निर्णायक भूमिका है। ईरान, दुनिया में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, जबकि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ईरानी तेल की चीन में खपत से तेहरान के ख़िलाफ वाशिंगटन के प्रतिबंध नाकाम होकर रह जायेंगे। चीन की BRI पहल के हिस्से के रूप में ईरान और चीन के बीच हस्ताक्षरित बहुप्रतीक्षित 25 वर्षीय रणनीतिक सहयोग समझौता के द्वारा चीन के लिए अफ़ग़ानिस्तान सहित खाड़ी देशों में अमेरिका की रिक्तता को भरने में भी मदतगार साबित होगा। जहाँ एक ओर यह क्षेत्र चीन की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए चीनी सामानों एवं हथियारों का एक बड़ा बाजार हो सकता है वहीं दूसरी ओर शक्ति प्रदर्शन के लिए एक अखाड़ा भी हो सकता है। ब्रेज़िंस्की, एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ईरान को एक धुरी राज्य के रूप में वर्गीकृत करते हैं, उन्होंने को ईरान एक ऐसे राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया गया है "जिसका महत्व उनकी शक्ति और प्रेरणा से नहीं बल्कि उनके संवेदनशील स्थान से है" चूँकि भू-राजनीतिक धुरीयाँ अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अपना महत्व रखती हैं, वे या तो महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक पहुँच को सुविधाजनक बनाने या प्रभावशाली अभिनेताओं के लिए संसाधन पहुँच को बाधित करने में एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं।[10]

निष्कर्ष:-

ईरान में चीन का निवेश चीन की कई सपनों को संजोए हुए है जिसको पूरा करने के लिए उसने अपने महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एण्ड रोड इनीशिएटिव को लांच किया है। खाड़ी देशों की भू-राजनीति को नियंत्रित करने के लिए इस क्षेत्र में चीनी परियोजनाओं का संचालन काफी अहम है। चीन में तेल खपत का अधिकांश आपूर्ति इन्हीं खाड़ी देशों से होता है जिनमें ईरान, चीन का प्रमुख तेल निर्यातक देश है। चीन की इस क्षेत्र में उपस्थिति न सिर्फ भारत के व्यापारिक हितों को प्रभावित करेगा बल्कि चीन की खूफिया जहाज सुरक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित भारतीय आसूचना संचार तंत्र को भी प्रभावित करेगा।

भारत को अपनी वैदेशिक नीति को स्वतंत्र रूप से संचालित करनी चाहिए ताकि राष्ट्रीय हितों को मजबूती से साधा जा सके। भारत और ईरान महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार हैं। भारत व्यापार के क्षेत्र में ईरान का सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक रहा है। भारत में कच्चे तेल की सबसे ज्यादा आपूर्ति ईरान के द्वारा ही किया जाता है। हालांकि अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रतिबन्ध के कारण भारत के द्वारा कुछ समय के लिए तेल का आयात रूस की तरफ हो गया है। भारत को अपनी वैदेशिक परियोजनाओं (यथा- चाबहार बंदरगाह, आईएनएसटीसी, ज़ाहेदान रेलवे प्रोजेक्ट आदि) को विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य करना होगा, ताकि ईरान समेत सभी पश्चिम एशिया के देशों को यह यकीन हो जाए कि भारत अपनी परियोजनाओं को लेकर प्रतिबद्ध है।

सन्दर्भ:-

1. (2020). India-Iran Relations. *Embassy of India*, p-1, URL- https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/India-Iran__Aug_2020_.pdf
2. D L Berlin. (2004). India-Iran Relations: A Deepening Entente. Asia-Pacific Centrer for Security Studies, p-5,
3. (2022). India-Iran Relations. Embassy of India Tehran, p-2, URL- https://www.indianembassytehran.gov.in/eoithr_pages /MTY
4. Seshadri Chari. (2021). New China-Iran pact brings a headache for India; It's not just another international deal. *The Print*, URL- https://theprint.in/opinion/new-china-iran-pact-brings-a-headache-for-india-its-not-just-another-international-deal/632552/
5. (2022). India-Iran Relations. Embassy of India Tehran, p-2, URL- https://www.indianembassytehran.gov.in/eoithr_pages /MTY
6. Abhijit Singh. (2020). With India-US badly coordinated in Indian Ocean, China-Iran naval ties now a fresh concern. *The Print*, URL- https://thep rint.in/opinion/with-india-us-badly-coordinated-in-indian-ocean-china-iran-naval-ties-now-a-fresh-concern/471934/?amp
7. Suhasini Haidar. (2020). Iran drops India from Chabahar rail project, cites funding delay. *The Hindu*, URL- https://www.thehindu.com/news/national/iran-drops-india-from-chabahar-rail-project-cites-funding-delay/article32072428.ece
8. Deniz Unver.(2023). International North-South Transit Corridor (INSTC). *AVRASYA INCELEMELERI MERKEZI*, p-1, URL- https://avim.org.tr/B log/INTERNATIONAL-NORTH-SOUTH-TRANSIT-CORRIDOR-INSTC-06-07-2023
9. Abhinandan Mishra. (2021). Chinese influence led Iran to sideline India. *The Sunday Guardian*, URL- https://www.sundayguardianlive.com/news/chinese-influence-led-iran-sideline-india
10. Sankalp Gurjar. (2023). The Iran Challenge: Unraveling India's Foreign Poicy Dilemma. *Journal of Indo-Pacific Affairs*, p-2-3